ग्रामीण क्रेडिट से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और मजबूत संस्थागत ढांचे से गांवों तक पहुंच रही आसान वित्तीय सुविधा

नई दिल्ली, 16 जुलाई. भारत में ग्रामीण क्रेडिट व्यवस्था ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है. किसानों, छोटे कारोबारियों, ग्रामीण उद्यमियों और परिवारों को खेती, रोजगार, निवेश और घरेलू जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में ग्रामीण ऋण प्रणाली अहम भूमिका निभा रही है.

पिछले कुछ दशकों में भारत की ग्रामीण ऋण व्यवस्था अनौपचारिक उधारी से आगे बढ़कर एक मजबूत संस्थागत प्रणाली में बदल गई है. आज वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण

> सहकारी बैंक छोटे किसानों और कमजोर वर्गों तक ऋण पहुंचाने का प्रमुख माध्यम हैं. इनमें राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं .स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और कमजोर वर्गों को कम लागत वाली बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराती है .

बैंक , सहकारी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुंचाने का काम कर रहे हैं.सरकारी योजनाओं, डिजिटल तकनीक और वित्तीय समावेशन अभियानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की पहुंच लगातार बढ़ रही है. इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर और समय पर वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे कृषि उत्पादन, रोजगार और छोटे व्यवसायों को नई गति मिल रही है.

भारत की ग्रामीण क्रेडिट प्रणाली में पिछले वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और छोटे कारोबारी साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भर रहते थे. अब बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी योजनाओं के कारण औपचारिक ऋण व्यवस्था मजबूत हुई है.

निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क सात रुपये बढ़ा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. सरकार ने निर्यात किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क की दरों में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, नयी दरें 16 जुलाई जुलाई से प्रभावी हो गयी हैं. निर्यात वाले डीजल और एटीएफ पर उत्पाद शुल्क सात-सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है. वहीं, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गयी है. अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात होने वाले पेट्रोल पर गुरुवार से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क चार रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है. डीजल पर एसएईडी 8.50 रुपये के बढ़ाकर 15.50 रुपये और विमान ईंधन पर 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

पेट्रोलियम निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव

घरेलू ईंधन आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर

भारतीय रिफाइनरियां निर्यात से अतिरिक्त लाभ कमा सकती हैं

नई दिल्ली, 16 जुलाई. सरकार के इस फैसले का देश के आम उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों या शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह कर केवल उन पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है जिन्हें भारतीय रिफाइनरी कंपनियां विदेशों में निर्यात करती हैं. इसलिए घरेलू वाहन चालकों और उद्योगों के लिए मौजूदा ईंधन कीमतों में तत्काल बदलाव की संभावना नहीं है.

सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दौरान भारतीय रिफाइनरियां निर्यात से अतिरिक्त लाभ कमा सकती हैं. ऐसे में निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाकर इस असाधारण लाभ को नियंत्रित किया जाता है. इस कदम का एक प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना भी है.

> डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है . इससे कंपनियों को घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा . वहीं, पेट्रोल पर शुल्क में कटौती से रिफाइनरी कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी . वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितताओं के बीच सरकार के ये नीतिगत बदलाव घरेलू ईंधन व्यवस्था को स्थिर रखने और अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकते हैं .

चीन की सैंदक खदान पर गहराया संकट

नई दिल्ली, 16 जुलाई. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन द्वारा संचालित सैंदक तांबा और सोना खदान परियोजना पर संकट मंडराने लगा है.

लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ती हिंसक घटनाओं के कारण परियोजना संचालित करने वाली कंपनी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो अगले एक महीने के भीतर खदान का उत्पादन पूरी तरह बंद करना पड़ सकता है.

बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठनों द्वारा चीन समर्थित परियोजनाओं को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है. सैंदक मेटल्स लिमिटेड ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि सुरक्षा चुनौतियों के कारण परियोजना के लिए जरूरी कच्चा माल, उपकरण और अन्य आवश्यक सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. इससे खदान का संचालन प्रभावित हो रहा है

सैंदक कॉपर-गोल्ड परियोजना वर्ष 2001 से चीन की सरकारी कंपनी मेटालर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना और पाकिस्तान की सरकारी कंपनी सैंदक मेटल्स लिमिटेड के संयुक्त संचालन में चल रही है. यह पाकिस्तान की प्रमुख तांबा और सोना खदान परियोजनाओं में शामिल है.

वीआईटी भोपाल में जीएनएसएस रिसीवर स्थापित

आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

सीहोर, 16 जुलाई. भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक सहयोगात्मक पहल के तहत वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम के अवलोकन के लिए अपनी 'उत्तर-दक्षिण आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम अवलोकन श्रृंखला' के अंतर्गत जीएनएसएस रिसीवर प्रणाली स्थापित की है.

यह अत्याधुनिक सुविधा विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इसके माध्यम से वीआईटी भोपाल

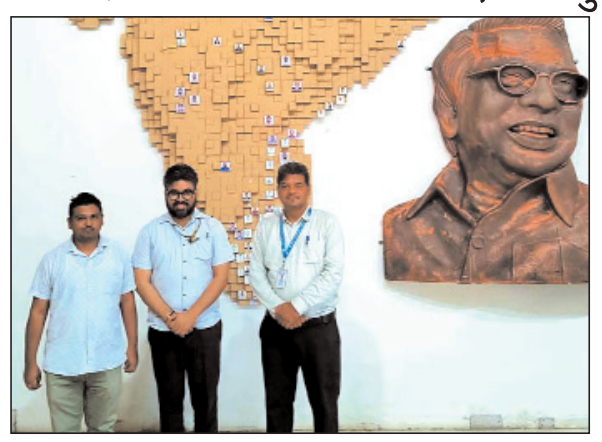

यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष मौसम, स्वदेशी नेविगेशन तकनीकों और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा. स्थापित किया गया जीएनएसएस रिसीवर आयनोस्फीयर से जुड़े महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी करने में सक्षम होगा. इसमें कुल इलेक्ट्रॉन सामग्री , आयनोस्फेरिक झिलमिलाहट, संकेत क्षरण, संपर्क समाप्ति और भूमध्यरेखीय प्रक्रियाओं के साथ-साथ सूर्य एवं भू-चुंबकीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले गतिशील आयनोस्फेरिक विक्षोभ का अध्ययन शामिल है.

> वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में स्थापित एक बहुविषयक विश्वविद्यालय है, जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समूह की विरासत को आगे बढ़ा रहा है . 300 एकड़ में फैले हरित परिसर में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित करता है .विश्वविद्यालय में सभी शिक्षक डॉक्टरेट योग्यता रखते हैं .

श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय बना वैश्विक आयुर्वेद

हरिद्वार, 16 जुलाई. हरेला पर्व के पावन अवसर पर देश के एकमात्र हर्बल वर्ल्ड 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वृहद् पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृहद पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' आयुर्वेद के जनक और आरोग्य के शाश्वत प्रतीक भगवान धन्वंतरि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी ने कहा कि यह इकाई हर्बल जगत में दुनिया का पहला जीवंत उद्यान होगी जहाँ विविध भौगोलिक क्षेत्रों से पौधे एकत्रित किए जाएँगे. स्वामी जी ने कहा कि 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' केवल वनस्पतियों का केंद्र नहीं है; यह वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का एक आंदोलन है. वहीं, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि इस धाम में 9 चिकित्सा पद्धतियाँ और विश्व की लगभग 964 चिकित्सा विद्याएँ को समाहित किया गया है. 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' एक ऐतिहासिक पहल तथा अतीत व भविष्य के बीच एक सेतु है.

मुख्य अतिथि श्री धामी ने कहा कि हम यहाँ एक उद्यान अथवा एक संस्थान की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के उस महान संकल्प, विराट दृष्टि और सभ्यतागत चेतना के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं, जो भारत की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है.

> **'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का आंदोलन : स्वामी रामदेव-** कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि 'श्री धन्वंतरि धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय' आचार्य बालकृष्ण जी की दूरगामी सोच तथा अखण्ड-प्रचण्ड प्रयास का परिणाम है . यह इकाई हर्बल जगत में दुनिया का पहला जीवंत उद्यान होगी जहाँ विविध भौगोलिक क्षेत्रों से पौधे एकत्रित किए जाएँगे . स्वामी जी ने कहा कि 'हर्बल वर्ल्ड हिमालय' केवल वनस्पतियों का केंद्र नहीं है . यह वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चेतना का एक आंदोलन है . यह हमें याद दिलाता है कि यदि हम प्रकृति को बचाएँगे, तभी प्रकृति हमें बचा पाएगी .

पोस्ट ऑफिस योजना से हर महीने पाएं तय कमाई

मासिक आय के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प

जानें ब्याज और रिटर्न का पूरा गणित

नई दिल्ली, 16 जुलाई. अगर आप अपनी बचत पर हर महीने नियमित आय चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना एक लोकप्रिय विकल्प हो सकती है. यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से बचते हुए सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं.

इस योजना में एकमुश्त निवेश करके हर महीने ब्याज के रूप में आय प्राप्त की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में निवेश की गई राशि पर सरकार द्वारा तय ब्याज दर के अनुसार मासिक भुगतान मिलता है. वर्तमान में इस योजना पर 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर उपलब्ध है. हालांकि ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है,

> पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में कोई भी पात्र भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है . इसमें व्यक्तिगत खाते के अलावा संयुक्त खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध होती है . यह योजना कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में शामिल है . जिन निवेशकों की प्राथमिकता पूंजी की सुरक्षा और नियमित आय है, उनके लिए यह योजना एक बेहतर विकल्प हो सकती है . हालांकि निवेश से पहले अपनी वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार योजना का मूल्यांकन करना जरूरी है .

5 साल से छोटे बच्चे का ऐसे बनवाएं आधार कार्ड

नई दिल्ली, 16 जुलाई. आज के समय में छोटे बच्चों के लिए भी आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है. अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आप उसका बाल आधार कार्ड बनवा सकते हैं. यह आधार कार्ड कई सरकारी योजनाओं, स्कूल प्रवेश और अन्य जरूरी कामों में उपयोगी होता है. बाल आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है. इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है. यह सामान्य आधार कार्ड से अलग होता है.

सेंसेक्स शुरुआती तेजी के बाद हुआ बंद

मुंबई, 16 जुलाई. विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बिकवाली हावी रही, हालांकि आईटी और ऑटो सेक्टरों में लिवाली से प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 203 अंक की मजबूती के साथ खुलने के बाद दोपहर तक बढ़त में बना रहा. दोपहर बाद बिकवाली का दबाव बढ़ने से सूचकांक अंत में मात्र 1.44 अंक ऊपर 77,186.87 अंक पर बंद हुआ.

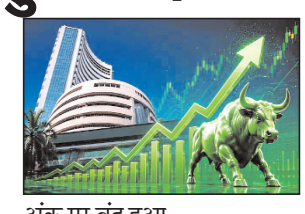

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी दोपहर तक हरे निशान में रहने के बाद बिकवाली के दबाव में 5.75 प्रतिशत यानी 0.02 फीसदी टूटकर 24,072.75 अंक पर आ गया.

समाचार विशेष

महागठबंधन में नहीं दिख रही एकता

परिसीमन को लेकर सभी दल एकमत होते नजर नहीं आ रहे

रांची. झारखंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नये सिरे से होने वाले परिसीमन को लेकर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है. सामाजिक संगठनों के साथ-साथ अब राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर गोलबंद होने लगे हैं हालांकि महागठबंधन के अंदर इस मुद्दे पर सभी दल एकमत नहीं होते दिख रहे हैं.

परिसीमन शुरू होने से पहले इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है. झामुमो ने प्रस्तावित परिसीमन के मसौदा का इंतजार करने की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी का मकसद आदिवासी और एससी सीटें घटाने का है, जिसे वो जानते हैं कि जीत नहीं पाएंगे क्योंकि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी के सर्वमान्य नेता हैं. ऐसे में यदि ऐसा होता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जबरदस्त विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में इस मुद्दे पर मतांतर होने पर भी हम अलग ढंग से इसके विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग इनकी चाल को समझते हैं.

इधर, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रिया है लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसका जरूर ध्यान केंद्र सरकार को रखना होगा. महागठबंधन के सहयोगी दल राजद ने परिसीमन पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम इसके विरोधी नहीं हैं लेकिन बीजेपी की नीति और नीयत में जो खोट है, उसका हम विरोध करते हैं. राजद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू कहते हैं कि पिछली बार जिस तरह से सदन में महिला आरक्षण बिल के बहाने लाया गया परिसीमन के ड्राफ्ट से सभी को पता चल गया है कि बीजेपी की मंशा क्या है. जम्मू-कश्मीर और असम में हुए परिसीमन इसके उदाहरण हैं, जो लगता है कि मतलब परस्त लोगों ने बनाया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी एक भी सीट ना हारे.

आदिवासी संगठन कर रहा परिसीमन का विरोध

वर्तमान में कुल 81 विधानसभा की सीटों में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति (स्ञ) और 9 सीटें अनुसूचित जाति (स्ट) के लिए आरक्षित हैं . नये परिसीमन में एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 28 से घटकर लगभग 21 होने की आशंका जताई जा रही है . इसी तरह राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें सामान्य- 8, अनुसूचित जनजाति-5 और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है . आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे राज्य में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाएगी .

विजय को अपने दम पर मिलेगा बहुमत

एआईएडीएमके के 10 और विधायक सीएम के समर्थन में छोड़ेंगे ईपीएस का साथ

चेन्नई. तमिलनाडु में थलपति विजय की अगुवाई वाली टीवीके जल्द अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है. राज्य में खाली हुई सात विधानसभा सीटों के कारण पहले ही बहुमत के करीब खड़े विजय की टीवीके जल्द बड़ा खेला सकती है.

तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के अंदरूनी लोगों अनुसार ऑपरेशन एल अब अंतिम दौर में है. एआईएडीएमके के 10 विधायक जल्द ही पाल बदल सकते हैं. सूत्रों की मानें तो

15 अगस्त तक टीवीके ऑपरेशन पूरा हो सकता है. एआईएडीएमके के विधायकों की संख्या घटकर 41 रह गई है, जिससे पार्टी के कई विधायकों को भविष्य में चुनावी नतीजों को लेकर चिंता सता रही है.टीवीके नेताओं और बागी एआईएडीएमके विधायकों के बीच चल रही बातचीत से जुड़े कई सूत्रों के मुताबिक विपक्षी पार्टी के करीब 10 विधायक 15 अगस्त से पहले अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा देकर औपचारिक रूप से सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि ये इस्तीफे चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा उपचुनावों के अगले दौर की संभावित घोषणा के साथ हो सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत में शामिल एक वरिष्ठ नेता के हवाले से लिखा है कि यह प्रक्रिया काफी हद तक स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी हो जाएगी.

> **विजय की कैबिनेट में मिल सकती है जगह**
>
> टीवीके और एआईएडीएमके के सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि सीवी शनमुगम और एस पी वेलुमणि भी जुलाई के आखिर या अगस्त की शुरुआत में टीवीके में शामिल हो जाएंगे . सूत्रों का कहना है कि बातचीत सिर्फ़ पार्टी बदलने तक ही सीमित नहीं है . जो लोग अपनी विधानसभा सीट छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें टीवीके के टिकट पर होने वाले उपचुनावों में दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा .

दक्षिण के मुख्यमंत्रियों की दोस्ती

नई दिल्ली. उत्तर भारत में आमतौर पर यह देखने को नहीं मिलता है कि मुख्यमंत्रियों के बीच आपस में बहुत सद्भाव और दोस्ती हो. अगर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के हैं तो अलग बात है लेकिन अगर मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टी के हैं तो उनको बीच कोई दोस्ती नहीं दिखती है.

कम से कम सार्वजनिक जगहों पर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो वे एक दूसरे की तारीफ नहीं ही करते हैं. परंतु दक्षिण भारत में इसका उलटा होता है. वहां एक दूसरे की विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्रियों में भी पूरा सद्भाव दिखाई देता है. वे सार्वजनिक जगहों पर भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं. दक्षिण के राज्यों का भाईचारा इससे प्रकट होता है.

पिछले दिनों तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री एक मंच पर थे. वहां तीनों ने एक दूसरे की जम कर तारीफ की. तेलंगाना और कर्नाटक में तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अलग है और वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का मुख्य घटक दल हैं. लेकिन नायडू ने रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार दोनों की जम कर तारीफ की.

विशेष | **अखिलेश यादव पर क्यों हमलावर हैं सुभासपा प्रमुख?**

बीजेपी का गेम प्लान या ओपी की मजबूरी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए अपनी रणनीतियों को आखिरी रूप देने का जुटी है. वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं.

हालांकि, पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति में ओमप्रकाश राजभर खूब चर्चाओं में हैं. वे लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला कर रहे हैं. लेकिन, सवाल उठता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में अखिलेश के साथ रहने वाले राजभर उनके खिलाफ

इतना हमलावर क्यों हैं. क्या यह बीजेपी का कोई सियासी चाल है या सुभासपा प्रमुख की अपनी मजबूरी ?

'पीडीए' के अभेद्य किले में सेंधमारी

अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय से 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा काफी प्रमुखता से बुलंद किया है. समाजवादी पार्टी के इस नए सियासी गणित ने 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था. हालांकि, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती, जिससे की उसको नुकसान हो. भाजपा अब इस सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है. सियासत के इस खेल में ओमप्रकाश राजभर एक बेहद अहम मोहरा बनकर उभरे हैं.

पूर्वांचल में सपा को रोकने की कोशिश- ओमप्रकाश राजभर खुद राजभर समाज (जो अति-पिछड़ी जाति में आता है) के बड़े नेता माने जाते हैं. बीजेपी राजभर के सहारे यादव वोट बैंक से अलग अन्य गैर-यादव ओबीसी जातियों को एकजुट रखना चाहती है. अखिलेश यादव लगातार सरकार पर पिछड़ों और दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते हैं. ऐसे में बीजेपी के पास ओपी राजभर के रूप में एक ऐसा आक्रामक चेहरा है, जो अखिलेश को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता है. पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर और अन्य अति-पिछड़ी जातियों की आबादी निर्णायक भूमिका में है. बीजेपी राजभर को आगे रखकर पूर्वांचल में सपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहती

> **अखिलेश को कहां घेर रहे हैं राजभर?**
>
> ओपी राजभर अपने भाषणों और बयानों में बहुत सधे हुए तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं . राजभर अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट और एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं और पिछड़ों के बीच वह नहीं जाते . राजभर लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा का 'पीडीए' सिर्फ एक छलावा है और सत्ता में आने पर इसका फायदा सिर्फ एक विशेष जाति को ही मिलता है, अति-पिछड़ों को नहीं .